

क्रमांक एफ-28/4/11/यो/19 2618

भोपाल दिनांक 5-5-12

प्रति,

प्रमुख अ.ि.यंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषय: निर्माण कार्यों के नियोजन हेतु सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल कन्सलटेन्ट्स (SQC) पर किये जाने वाले व्यय के संबंध में।
संदर्भ: आपकी टीप क्रमांक 301/070/2011/1021 दिनांक 16.04.2012

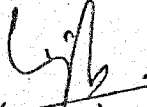
-0-

राज्य शासन एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल कन्सलटेन्ट्स (SQC) को अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति प्रदान करता है:-

- 1/ रुपये 10.00 करोड़ (रुपये दस करोड़) से अधिक लागत के सड़क तथा पुल के नवीन कार्यों में यह व्यवस्था "पायलट बेसिस" पर रखी जाए।
- 2/ सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल कन्सलटेन्ट्स (SQC) को अनुमोदित करने के लिये खुली (Open) निविदा पद्धति अपना जाये।
- 3/ कार्यों के प्राक्कलन में इस हेतु लागत राशि के अधिकतम 2% (दो प्रतिशत) राशि की सीमा में प्रावधान रखा जाये।

सहपत्र:- शून्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आरो के मेहरा)

अपर सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक

पृ. क्रमांक / 3099 / यो / 19 / 12
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 261/70/2/बी-9/चार दिनांक 02.05.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2- निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

सहपत्र:- शून्य

अपर सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग